State Government may consider permitting the commercial use and in lieu of that, colonisers may construct EWS/LIG houses. Succesful models such as those in Haryana and Maharashtra etc., may be taken into consideration while making such schemes.

These guidelines are recommendatory in nature and it would be the prerogative of the State governments to make suitable amendments and additions as per their requirements. The ultimate objective would be social equality.

लघु और कुटीर उद्योगों को बढावा दिया जाना

*276. **श्री ईश दत्त यादव** :

चौधरी हरमोहन सिंह यादव :

क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने हेतु कोई नीतिगत निर्णय लिया हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इन उद्योगों को केवल ग्रामीण क्षेत्रों में ही स्थापित किए जाने का प्रस्ताव हैं;

(ग) क्या इस संबंध में राज्य सरकारों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) क्या नौंवी योजना में लघु और कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के संबंध में कोई अनुमान लगाए गए हैं; और

(ड.) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उद्योग मंत्री (श्री सिकन्दर बख्त) : (क) जी हां। लघु, अत्यन्त लघु और ग्रामीण उद्यगों के संवर्धन और सुदृढ़ीकरण के लिए नीतिगत उपायों की घोषणा 6 अगस्त, 1991 को की गई थी।

(ख) जी, नहीं। तथापि, वित्त मंत्री ने केन्द्रीय बजट 1999-200 में "ग्रामीण औद्योगिकरण" के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम" नामक एक नई योजना की घोषणा की थी जिसका उद्देश्य ग्रामीण औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए हर वर्ष 100 ग्रामीण समूहों की स्थापना करना हैं। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) इसमे एक महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगा। इस दिशा में खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग के पास उपलब्ध विपणन अवसंरचना ग्रामोद्योग आयोग के पास उपलब्ध विपणन अवसंरचना का अधिकतम प्रयोग किया जायेगा। उच्च संभाव्यता वाले और पिछड़े ग्रामीण क्षेत्रों के बीच उचित सन्तुलन रखकर देश भर में ग्रामीण समूह फैलाये जायेंगे।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ड.) लघु और कुटीर उद्योग क्षेत्र के संवर्धन और विकास के लिए नौवी योजना में 4303.85 करोड़ रू.आवंटित किए गये हैं। इसमें निम्नलिखित योजनाओं/कार्यक्रमों तथा अन्य सहायक सेवाओं को जारी रखना शामिल हैं, जैसे:-

- ग्रामीण तथा पिछड़े क्षेत्रों के अवसंरचना सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए एकीकृत अवसंरचना विकास कार्यक्रम।

- राज्यों में अति लघुं औजार कक्षों और प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना करना।

- लघु उद्योगों की, समूह आधार पर प्रौद्योगिकी उन्नयन और आधुनिकीकरण कार्यक्रम में सहायता करना।

- लघु उद्योग सेवा संस्थानो से जुड़ी 42 कार्यशालाओं का उन्नयन।

- औजार कक्षों तथा परीक्षण केन्द्रों में उपलब्ध सुविधाओं का उन्नयन करना।

- प्रधान मंत्री रोजगार योजना (पीएमआरवाई) के कार्यान्वयन के माध्यम से सूक्ष्म उद्यमो के विकास को सरल बनाना।

PSUs in Maharashtra

*277. SHRI SURYABHAN PATIL VAHADANE: Will the Minister of INDUSTRY be please to state:

(a) the total number of industries under public sector in Maharashtra;

(b) how many of these arc earning profit;

(c) how many are running in losses; and

(d) the efforts made by Government to make public sector undertakings profitable in Maharashtra alongwith the details thereof?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI SIKANDER BAKHT): (a) to (c) As per the Public Enterprises Survey 1997-98 which was laid on the table of